जयपुर दौरे पर आए भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का भव्य स्वागत

नड्डा भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने आए हैं

जयपुर, 23 जनवरी (का.सं.)। भाजपा राजस्थान प्रदेश कार्यसमिति बैठक को संबोधित करने जयपुर आये भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने राजस्थानी साफा और पार्टी का दुपट्टा पहनाकर जेपी नड्डा का स्वागत किया।

- **प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर भी जोरदार हमला बोला और आह्वान किया कि आगामी चुनावों में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है।**
- **नड्डा ने कहा कि, जनसंघ से लेकर भाजपा तक राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने में सुंदर सिंह भंडारी, भैरोसिंह शेखावत, भंवर लाल शर्मा और ललित चतुर्वेदी के भारी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।**

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने सोमवार को जयपुर में राजस्थान प्रदेश कार्यसमिति की बैठक ली। उनके साथ बी.जे.पी. प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे।

भाजपा राजस्थान प्रदेश कार्यसमिति बैठक को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया और कहा कि वीरों की भूमि मरुधरा पर भव्य आत्मिक स्वागत-अभिनंदन के लिए राजस्थान के करोड़ों कार्यकर्ताओं और पावन धरा राजस्थान को वंदन एवं प्रणाम करता हूं। भाजपा राजस्थान इकाई द्वारा किए गए तमाम आंदोलनात्मक और संगठनात्मक कार्यक्रमों के लिए मैं प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश टीम और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। नड्डा ने कहा कि हर किसी को विधायक और सांसद बनने की चाहत है। मगर मेरा मानना है कि सभी को नेता बनना चाहिए। पद अपने आप मिल जाएगा।

उन्होंने कहा कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मजबूत करने में सुंदर सिंह भंडारी, भैरोंसिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है, पॉलिटिक्स विद मिशन, पॉलिटिक्स विद आईडियोलॉजी के साथ हम काम करते हैं, देश की सेवा, पार्टी और विचारधारा हमारे लिए सर्वोपरि है। लक्ष्य हमेशा विचारधारा की मजबूती का लेकर चलें, कैडर की मजबूती का लेकर चलें, क्योंकि हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कैडर मजबूत होगा तो आप अपने आप मजबूत हो जाएंगे, पार्टी मजबूत होगी तो आप अपने आप मजबूत हो जाएंगे, पार्टी सर्वोपरि है।

नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है और हम प्रजातांत्रिक तरीके से कैडर की मजबूती के लिए कार्य करते हैं, भाजपा एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है बाकी सभी पार्टियां फैमिली पार्टी बनकर रह गई हैं, कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो चुकी है, एक फैमिली की पार्टी के रूप में कांग्रेस की पहचान बन चुकी है, रीजनल पार्टियां भी फैमिली पार्टी बन कर रह गई हैं।

कांग्रेस को यही नहीं पता कि वह किसको जोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं, राहुल गांधी की पूरी यात्रा में दाएं बाएं वही लोग चले जिन्होंने भारत के खिलाफ नारे लगाए, भारत के खिलाफ साजिशें की।

भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात के लिए संकल्पित हूं कि अंतिम सांस तक पार्टी के लिये कार्य करूंगा, सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी लक्ष्य के साथ काम करें। बड़े लक्ष्य के लिए बड़ा दिल लेकर और बड़े मन से कार्य करें और मिशन 2023 और 2024 के लिए संकल्पित होकर कार्य करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2023 में राजस्थान और 2024 में केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बने इसके लिए पूरी मजबूती से कार्य करें।

उन्होंने कहा कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के शासन में राजस्थान के बदतर हालात हैं, जिसमें महिला अपराध, दलित अपराध, साइबर अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी जनविरोधी और कुशासन देने वाली कांग्रेस सरकार को हमें उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़नी है, इसको जनता के बीच जाकर एक्सपोज़ करते रहना है।

महारानी कॉलेज छात्रसंघ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्मल चौधरी को महासचिव अरविंद जाजड़ा ने थप्पड़ मार कर नीचे गिरा दिया। घटना को लेकर दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए और मंच पर तोड़फोड़ कर दी। उधर कॉलेज प्रशासन और निर्मल चौधरी की ओर से घटना को लेकर अशोक नगर थाने में अलग-अलग मुकदमें दर्ज कराए गए हैं।

कार्यक्रम समाप्ति से कुछ देर पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी मंच पर पहुंचे। इस दौरान महासचिव अरविन्द जाजड़ा ने निर्मल चौधरी को थप्पड़ मारकर मंच से धक्का दे नीचे गिरा दिया। इस घटना के बाद निर्मल समर्थक आक्रोशित हो गए और उन्होंने मंच पर चढ़कर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य लोग मंच पर ही मौजूद थे। देखते ही देखते निर्मल समर्थकों ने मंच को पूरी तरह से तोड़ दिया और वहां लगी टेबल, कुर्सी, नेम प्लेट, साउंड सहित सबको नीचे फेंक दिया। इस दौरान निर्मल और जाजड़ा समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से जमकर मारपीट हुई। हंगामे को बढ़ता देख केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य अतिथि मंच से उतरकर चले गए। पूरी घटना को वहां मौजूद पुलिस और कॉलेज प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा। गनीमत रही कि मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य अतिथियों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई।

जिस समय यह घटना हुई कार्यक्रम समाप्ति पर था। कुलपति प्रो. राजीव जैन समापन भाषण दे रहे थे। इसी बीच आरयू छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी समर्थकों के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंच पर पहुंचे। निर्मल मंच से हाथ हिलाकर छात्राओं का अभिवादन कर रहे थे, कि इसी दौरान जाजड़ा ने निर्मल को थप्पड़ मारकर मंच से गिरा दिया।

- **कॉलेज प्रशासन ने भी कार्यक्रम में छात्रों द्वारा मारपीट करने और मंच पर तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज कराया है।**
- **दुखद बात यह भी है कि, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मंच पर मौजूद थे, जब यह घटनाक्रम हुआ।**

घटना के बाद निर्मल चौधरी ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में पुलिस के सामने असामाजिक तत्व इस प्रकार गुंडागर्दी कर रहे है। ऐसे हालात पहले नक्सली क्षेत्रों में थे, वैसे अब राजस्थान में होते जा रहे है। यह पुलिस प्रशासन की नाकामी का परिणाम है। मुझे कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। मैं इस घटना से डरने वाला नहीं हूं, छात्र शक्ति के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। इधर निर्मल चौधरी की तरफ से अशोक नगर थाने में अरविंद जाजड़ा के खिलाफ मारपीट का जबकि कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्रों के खिलाफ मारपीट व तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

कार्यक्रम में हंगामा होने के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शेखावत के निकलने के साथ ही कुलपति प्रो. राजीव जैन और कॉलेज प्राचार्य प्रो. मुक्ता अग्रवाल सहित अन्य विश्वविद्यालय शिक्षक भी चले गए। प्रो. मुक्ता अग्रवाल अपने ऑफिस में आकर बैठ गई, वहीं कुलपति भी विश्वविद्यालय चले आए। जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वे मौके पर उपस्थित होकर छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करते। उनके जाने के बाद भी छात्रों की बीच मारपीट होती रही। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद छात्राएं दहशत में आ गई।

इस घटना के बाद निर्मल का एक वीडियो पुलिस के बीच जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो उस समय का है जब छात्रसंघ चुनाव की मतगणना के बाद जब निर्मल चौधरी छात्रसंघ अध्यक्ष पद विजयी हुए थे। विजयी होने के बाद पुलिस जवान शपथ दिलाने के लिए निर्मल को लेकर जा रहे थे। उस दौरान निर्मल पुलिस को धमकाते हुए दिख रहे है।

कार्यक्रम में हंगामा होने के बाद एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हुश्यार मीणा कार्यकर्ताओं के साथ महारानी कॉलेज पहुंचे। महासचिव अरविन्द जाजड़ा को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के छात्र प्रिसिंपल प्रो. मुक्ता अग्रवाल के चैंबर में घुस गए। इस दौरान पुलिस छात्रों को खदेड़कर बाहर ला रही थी, तभी धक्का-मुक्की में सीआई नेमीचंद सीढ़ियों से नीचे गिर गए और उनके उपर एक छात्र भी गिर गया। नेमीचंद सिविल ड्रेस में थे, इस इस कारण पुलिस जवान भी उन्हें पहचान नहीं पाए और उन पर भी लाठीचार्ज कर दिया। गिरने से नेमीचंद के पैर में भी चोट आई है।

एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हुश्यार मीणा ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना का विद्यार्थी परिषद् निंदा करती है। दोनों ही पार्टी के नेताओं को भी कॉलेज व विश्वविद्यालय कैंपस में इस प्रकार के कार्यक्रम में आने से बचना चाहिए। वहीं अध्यक्ष और महासचिव दोनों का ही बराबर का अधिकार है, दोनों को ही मंच पर समान रूप से बिठाना चाहिए। महारानी कॉलेज में छात्रों के प्रवेश पर रोक है। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने बाहरी छात्रों सहित विश्वविद्यालय के छात्रों को कॉलेज में प्रवेश देकर कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। छात्रसंघ पदाधिकारियों के साथ भी बढ़ी संख्या में छात्र वहां पहुंच गए। अगर बाहरी छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता तो, इस घटना को होने से रोका जा सकता था। वहीं केन्द्रीय मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने पर भी पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। महारानी कॉलेज में जब भी छात्रसंघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम होता है, वो हंगामे की भेट चढ़ जाता है। करोना से पहले भी तत्कालीन छात्रसंघ अध्यक्ष रितु बराला के कार्यालय उद्घाटन के दौरान हंगामा हुआ था।

'कमियों के बावजूद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लोकतंत्र के समान है जिसमें यह सभी खराब प्रणालियों के बीच एक सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन है। उन्होंने कहा कि एक मात्र अन्य विकल्प नैशनल जूडीशियल अपॉइन्टमैंट्स कमीशन (एन.जे.ए.सी.) है, लेकिन कोलीजियम सिस्टम इससे कम बुरा है।

शीर्ष अदालत में वर्ष 1993 में नरिमन ने ही एन.जे.ए.सी. का विरोध किया था। बार एण्ड लीगल वैबसाइट को दिए एक साक्षात्कार में नरिमन ने कहा कि "उन्होंने तर्क दिया था कि जजों की नियुक्ति जजों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे से बाद में जिस तरह से निबटा गया और विवाद पैदा हो गए, उसके आधार पर मैं इसी बात पर जोर दूंगा कि कोलीजियम ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।"

जब उनसे कोलीजियम की त्रुटियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरी कवायद यह सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए कि सिस्टम के अन्तर्गत सबसे बेहतर व्यक्ति को नियुक्ति मिले और जजों द्वारा कुछ जजों का चयन किए जाने में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि ऐसा हमेशा से हुआ है और आखिरकार जज भी तो मानव हैं।

सभी मैडिकल कॉलेजों को कहा गया है कि...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की एकमात्र प्राथमिकता चिकित्सा तथा मरीजों एवं डॉक्टरों के हित होने चाहिये।

फेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रोहनकृष्णन ने कहा, "मेरे ख्याल से तो एन.एम.सी. एवं स्वायत्तशासी, स्वतंत्र तथा राजनीति-निरपेक्ष निकाय की तरह काम नहीं कर रहा है। डॉ. कृष्णन, मौलाना आज़ाद मैडिकल कॉलेज, नई दिल्ली, जो केन्द्र सरकार का कॉलेज है, में ऑर्थोपैडिक सर्जन हैं।

उन्होंने कहा, "दुख का विषय है कि कमीशन, जिसकी स्थापना मैडिकल शिक्षा में सुधार तथा हर जगह हर व्यक्ति के लिये चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई थी, ने इस प्रकार का सर्कुलर जारी किया है। इस प्रकार का कोई भी सर्कुलर प्रदर्शित करता है कि एन.एम.सी. अफसरशाहों तथा पी.एम.ओ. को खुश करने की कोशिश कर रहा है।"

दो अन्य फेमा-सदस्यों ने कहा कि एन.एम.सी. को चिकित्सा-सुविधा एवं सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार करने पर ध्यान देना चाहिये।

एक तरफ, जहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये बजट-आवंटन कम होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ, अन्य सरकारी विभाग "सरकार के प्रति ज्यादा निष्ठा" दिखा रहे हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार द्वारा गत माह राज्यसभा में उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार, केन्द्र द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च, जो 2016-17 में भारत की जी.डी.पी. का 1.09 प्रतिशत था, गिरकर 2017-18 में 0.97 प्रतिशत तथा 2018-19 में 0.96 प्रतिशत रह गया। लब्धप्रतिष्ठ समाज विज्ञानी आन्द्रे बैतिलि ने कहा कि सरकार तथा रेग्यूलेटरी के लिये अनुचित है कि वह विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम को देखने के लिये सर्कुलर जारी करे।

बैतिलि ने कहा, "संस्थाएं यह निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होनी चाहिये कि वे विद्यार्थियों या फैकल्टी के लिये क्या कार्यक्रम आयोजित करना चाहती हैं। सरकार द्वारा रेग्यूलेट्री बॉडी को ऐसा जाने तथा रेग्यूलेटर्स द्वारा संस्थानों को ऐसा कहे जाने की प्रवृत्ति गलत एवं अस्वस्थ (परम्परा की शुरुआत) है।

पोस्ट ग्रेजूएट कर रहे मैडिकल छात्र कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में रेजिडैन्ट डॉक्टर्स की कमी उन महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है जो चिकित्सकों और रोगियों, दोनों को प्रभावित कर रहा है।

नई दिल्ली के ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेस (ऐम्स) के एक रेजिडैन्ट डॉक्टर ने कहा कि "रेजिडैन्ट्स की कमी का मतलब है कि डॉक्टर्स प्रत्येक रोगी को कम समय देने के लिए बाध्य हैं।

रेजिडैन्ट ने आगे कहा कि "हैल्थ केयर में कम व्यय, मानव संसाधन और चिकित्सकों की सुरक्षा नैशनल मैडिकल कमीशन की शीर्ष प्राथमिकताएं होनी चाहिए ना कि स्क्रीन्ड इवैन्ट्स का प्रोत्साहन।

एक केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान के एक प्रोफेसर ने कहा कि विडम्बना यह है कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से प्रचार पर जोर दे रही है और साथ ही शिक्षा के लिए फण्ड्स में भी कमी कर रही है।

प्रोफेसर ने नाम ना छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि "सरकारी विश्वविद्यालयों के पास फण्ड्स की कमी है। फण्डिंग में प्रत्येक वर्ष वास्तविक कमी आ रही है।" फिर भी सरकारी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए नियामक संस्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें सरकार की गलत प्राथमिकताओं की झलक दिखाई देती है। एफ.ए.आई. एम.ए. में चर्म रोग विशेषज्ञ एवं सलाहकार मनीष जांगड़ा ने कहा कि "राजधानी तक के सरकारी अस्पतालों में दवाईयां, उपकरण और स्टाफ की कमी है और एन.एम.सी. हैल्थ केयर में ढांचागत सुधार करने के बजाए प्रचार में भाग ले रहा है।"

शिक्षा मंत्रालय ने "परीक्षा में चर्चा" को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित संवाद के एक ऐसे कार्यक्रम की संज्ञा दी है जिसमें वे परीक्षा संबंधी घबराहट और स्कूल के बाद के जीवन पर देश और विदेश के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से वार्तालाप करते हैं।"

कार्यक्रम दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को होगा। इसके लिए 150 देशों के 3.1 मिलियन से अधिक विद्यार्थियों और 5 लाख 60 हजार शिक्षकों के अलावा 50 देशों के 1 लाख 95 हजार अभिभावकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है।

मंत्रालय ने कहा है कि "कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन को एक उत्सव की भांति मनाने को लेकर तनाव पर पार पाने में मदद करना है।"

मीडिया पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2015 के एक निर्णय की याद दिलाई जिसमें आई.टी. एक्ट की धारा 66ए को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि अनजाने में हुई गलतियां तर्कसंगत प्रतिबंधों का आधार नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि प्रैस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पी.आई.बी.) ऑनलाइन "फेक न्यूज़" को लेकर चेतावनी देता रहा है, लेकिन उसकी समझ को कई बार गलत पाया गया। उन्होंने कहा कि यदि मसौदा ही कानून बन जाता है तो ऐसी गलत राय को पलटा नहीं जा सकेगा क्योंकि इसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

लोकतांत्रिक नियम बनाए रखन को लेकर आई.जे.यू. ने कहा कि सरकार को ऑनलाइन गलत जानकारी या दुष्प्रचार पर निगरानी रखने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन करना चाहिए। उसने आगे कहा कि "फिर भी विधिक रूप से विवादित किसी विषय के नियमन का काम किसी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण का होना चाहिए ना कि सरकार का।"

भाजपा तमिलनाडू में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जो उसके प्रति सहानुभूति रखने वाला हो।

इस चैनल की लॉचिंग भाजपा की तमिलनाडु इकाई करेगी। ऐसी संभावना है कि यह टी.वी. चैनल "जनम टी.वी.) का ही विस्तार (एक्सटेंशन) होगा, जो केरल में भाजपा की आवाज माना जाता है। यह चैनल चेन्नई मे अल्वार पैट के बाहर किसी स्थान पर काम करेगा। चेन्नई के मीडिया विश्लेषकों का कहना है कि यह कोई चौंकाने वाली चीज नहीं है। अगर यह चैनल व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं भी रहता है, तो भी उसे काफी सहयोग एवं सम्बल मिल जायेगा क्योंकि भाजपा दिल्ली में सत्तारूढ़ है।

भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई इस टी.वी. चैनल प्रोजैक्ट को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक एवं उत्साहित हैं, जो भाजपा की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को व्यापक कवरेज देगा तथा 4 अप्रैल 2023 को शुरु होने जा रही उनकी राज्यव्यापी पदयात्रा को पूरी तवज्जो देते हुये, उसका प्रचार-प्रसार करेगा।

प्रसंगवश बात दें कि केरल में भी, जनम टी.वी. ने लोकल मीडिया में पार्टी का पला भारी रखा था तथा सबरीमाला केस को इसके द्वारा ही महत्ता के फलस्वरुप, इसके दर्शकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी तथा मुख्यधारा के मीडिया चैनलों की प्रतिस्पर्धा में आ गया था।

महाराष्ट्र के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केस में दी गई जमानत की पुष्टि की जाती है। इसके बाद, बैंच इस याचिका को सरसरी तौर पर खारिज करने लगी तथा यह स्पष्ट भी कर दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा किये गये विचारों से ट्रायल प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि वे विचार केवल जमानत के मुद्दे तक ही सीमित हैं। देशमुख 2 नवमबर, 2021 को हुई उनकी गिरफ्तारी के दिन से ही हिरासत में हैं। अक्टूबर, 2022 में, बम्बई उच्च न्यायालय ने मनीलॉण्डरिंग के एक केस में पूर्व गृह मंत्री को पहले ही जमानत दे दी थी। उस जमानत को रद्द करने से भी सर्वोच्च न्यायालय ने इंकार कर दिया था। देशमुख एक अन्य सी.बी.आई. केस के सिलसिले में जेल में थे।

कोटपूतली में तोड़फोड़ की घटनाओं का दौर फिर शुरू

तोड़फोड़ से प्रभावित व्यापारियों व मकान मालिकों में रोष व्याप्त

कोटपूतली, (निसं)। कस्बे में नगर परिषद् द्वारा कोटपूतली के मास्टर प्लान 2011-31 को लागू करने और सड़क चौड़ी करने के नाम पर पुलिस नगर पालिका तिराहे से आज़ाद चौक मार्ग के बीच बनी करीब 15 संरचनाओं को ध्वस्त किया।

गौरतलब है कि विगत अगस्त माह से परिषद् द्वारा मुख्य चौराहे से पुरानी नगर पालिका तिराहे तक सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के नाम पर व पूतली कट से बानसूर मोड खण्ड के सरदार स्कूल से शनि मंदिर तक की सड़क को 60 फीट चौड़ा करने के नाम पर भी कई इमारतों को गिराया था। यहां यह भी गौरफरमाने योग्य है कि इस कार्रवाई के खिलाफ करीब 100 से भी अधिक मामले में हाईकोर्ट में लंबित हैं। क्योंकि कई प्रभावित दुकानदार व मकान मालिकों का कहना है कि नगर परिषद् ने कार्रवाई करने से पूर्व नोटिस नहीं दिया है।

- **पुरानी नगर पालिका तिराहे से तहसील परिसर आजाद चौक मार्ग पर चला नगर परिषद का पीला पंजा।**
- **कोटपूतली में मास्टर प्लान के तहत संरचनायें तोड़ने का मामला, 15 संरचनाओं को ध्वस्थ किया।**
- **व्यापारी सूर्यकांत बिदाणी का इस कार्रवाई से सुरक्षा पाने के लिए मुंसिफ कोर्ट में दर्ज मामला लंबित था, प्रशासन ने उनकी भी दुकान तोड़ दी और घटनास्थल से जबरदस्ती उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया।**

उल्लेखनीय है कि मास्टर प्लान कार्यवाही के चतुर्थ चरण में पुरानी नगर पालिका तिराहे से आज़ाद चौक स्थित कचहरी परिसर के मार्ग को 40 फीट किया जाना है। वहीं आज़ाद चौक से अतिक्रमण हटाकर उसे पुराने मूल स्वरूप में लाना है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से पूर्व सड़क में बाधक बन रही 73 संरचनाओं को अक्टूबर माह में ही नोटिस जारी कर दिये गये थे, जिसके बाद व्यापारियों व संरचना मालिकों ने स्वयं के स्तर पर ही निर्माण हटाने का कार्य शुरू कर दिया।

अधिकारियों का कहना है कि लगभग 90 प्रतिशत से अधिक निर्माण हटाये जा चुके हैं। इसी को लेकर एक अतिक्रमण सहित शेष बच रही 15 संरचनाओं को हटाने की कार्यवाही सोमवार अल सुबह अंजाम दी गई। नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा के नेतृत्व में कार्मिकों समेत पुलिस का भारी जाप्ता उक्त मार्ग पर सोमवार तड़के पहुंचा, जहां निर्माण हटाये गये।

कस्बे के आज़ाद चौक में एक कथित निर्माण को हटाने के दौरान नगर परिषद अधिकारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान परिषद ने कचहरी के मुख्य द्वार पर निर्माणों को हटाया तो दुकान मालिक व्यापारी सूर्यकान्त बिदाणी ने एक पक्षीय कार्यवाही का आरोप लगाते हुए भारी विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने पहले तो उसे पीटा फिर हिरासत में ले लिया। व्यापारी का कहना है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से सुरक्षा पाने के लिए उन्होंने कोटपुतली मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका भी दायर कर रखी है, जिसकी सुनवाई 23 तारीख को ही थी। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें इस अदालत से अंतरिम रोक के आदेश प्राप्त नहीं हुए।

उन्होंने आगे बताया कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद नगर परिषद् ने सुबह 6 बजे आकर उनकी दुकान को ध्वस्त कर दिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जोर जबरदस्ती से खींचकर, मुजरिमों की मार्फत साढे 6 बजे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि उनकी गुहारों का किसी भी अधिकारी पर कोईअसर नहीं पड़ा, बल्कि उनके आत्मसम्मान, आत्मबल को कुचलते हुए पुलिस उन्हें घसीटते हुए थाने ले गई। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण से उनकी मानहानि हुई है। उन्होंने आगे बताया कि उनकी दुकाने के अन्दर पड़े सामान को किसी भी अधिकारी ने सुरक्षित रखने के लिए जब्त किया ना ही नगर परिषद की हिरासत में सौंपा। उनका कहना है कि ये सारा सामान स्थानीय गुण्डों व बाहुबलियों ने खुर्दबुर्द कर दिया या चोरी कर ली।

उन्होंने बताया कि उनका निर्माण 70 साल पुराना है और उनके पास 1958 की सेल की रजिस्ट्री भी है। परन्तु अदालत से राहत नहीं मिलने की वजह से प्रशासन आक्रामक तरीके से कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि उन्हें कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं मिला था, परन्तु पिछले शनिवार को ही नगर परिषद् के अधिकारियों ने उनकी दुकान के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। उनका कहना है कि जब तक अदातल में उनके द्वारा प्रस्तुत संपत्ति के कागजात को लगत नहीं ठहराया है, तो नगर परिषद् के ईओ उनकी इमारत तोड़ने का फैसला कैसे ले सकते हैं। कार्रवाई के दौरान जेसीबी, पौकलैड व एलएनटी मशीनों से आज़ाद चौक में विभिन्न दुकानों के सामने चबूतरे, सीढ़ी व टीन शेड़े आदि तोड़ते हुए अतिक्रमण हटाया गया।

साथ ही मुख्य राम चबूतरे व उसके पीछे स्थित पानी की टंकी को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान आयुक्त फतेह सिंह मीणा, एसडीएम ऋषभ मण्डल, तहसीलदार अभिषेक सिंह, एएसपी विधा प्रकाश, डीएसपी गौतम कुमार, आरएएस सृष्टि जैन, एसएचओ सवाई सिंह, नगर परिषद एक्सईएन दीपक मीणा, एईएन अनिल जोनवाल समेत भारी मात्रा में पुलिस जाप्ता व परिषद कार्मिक मौजूद रहे।

कोटपूतली नगरपालिका ने आज़ाद चौक पर सड़क किनारे बनी इमारतों और दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की।

कोटपूतली नगरपालिका ने सोमवार को तहसील कार्यालय के गेट के सामने बनी सूर्यकांत बेदाणी की दुकान तोड़ दी। सूर्यकांत बेदाणी की दुकान का मामला कोटपूतली मुनसिफ अदालत के समक्ष लंबित था। इन्होंने कार्यवाही के वक्त अपने सभी दस्तावेज भी प्रस्तुत किये लेकिन प्रशासन ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। सूर्यकांत बेदाणी ने प्रशासन के कर्मचारियों के समक्ष खूब मिन्नतें की, वे बेबस और असहाय होकर रोने और चिल्लाने लगे। पुलिस ने बाद में सूर्यकांत बेदाणी को हिरासत में ले लिया।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908